# संसद के समक्ष अभिभाषण – 5 जनवरी 1976

| | | |
|---|---|---|
| लोक सभा | - | पांचवीं लोक सभा |
| सत्र | - | वर्ष का पहला सत्र |
| भारत के राष्ट्रपति | - | श्री फख़रुद्दीन अली अहमद |
| भारत के उपराष्ट्रपति | - | श्री बी.डी. जत्ती |
| भारत की प्रधानमंत्री | - | श्रीमती इंदिरा गांधी |
| लोक सभा अध्यक्ष | - | श्री बलिराम भगत |

माननीय सदस्यगण,

मैं बहुत खुशी से आप सबका स्वागत करता हूं, खासकर सिक्किम के नुमाइन्दों का जो मई, 1975 में भारतीय यूनियन का 22वां राज्य बना। सरकार की यह कोशिश होगी कि इस पिछड़े पहाड़ी राज्य का तेजी से विकास हो।

पिछले साल, सरकार की मजबूत कार्रवाई की वजह से अर्थव्यवस्था में अच्छे नतीजों का जिक्र करते हुए मैंने आपका ध्यान कुछ जमातों की उन कोशिशों की तरफ दिलाया था जो मौजूदा निजाम और संस्थाओं को छिन्न-भिन्न करना चाहती थीं जिससे देश की तरक्की और पायदारी खतरे में पड़ गयी थी। मैंने उनसे अपील की थी कि तबदीलियां लाने के लिए वे बातचीत का रास्ता अपनायें और सुधार के लिए तजवीजों का स्वागत किया था। मुझे अफसोस है कि इस अपील पर कोई तवज्जो न दी गई। कुछ जमातें और ऐसे लोग, जिनके विचार एक-दूसरे से बिल्कुल अलग थे, देश के आर्थिक और राजनीतिक जीवन में रुकावट डालने के लिए आपस में मिल गए। उन्होंने लोगों के मन में गलतफहमी पैदा करने और बदअमनी फैलाने के लिए हर मौके का गलत फायदा उठाना चाहा। उनकी इन कार्रवाइयों से देश की अन्दरूनी सलामती बड़े खतरे में पड़ गई थी। उनका यह मकसद था कि किस तरह आर्थिक अपराध रोकने, पैदावार बढ़ाने और बढ़ती हुई इन्फ्लेशन पर काबू पाने, माल को सही ढंग और तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने, अर्थव्यवस्था को पायदार बनाने और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार की जोरदार कोशिशों को नाकाम बनाया जाये। देश के हित में कड़ा और फैसलाकुन कदम उठाना लाज़मी हुआ।

25 जून, 1975 के इमरजेंसी के एलान, 1 जुलाई, 1975 की 20-सूत्री आर्थिक प्रोग्राम की घोषणा और कौमी जिन्दगी के सभी क्षेत्रों में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए उठाये गए कदमों से राष्ट्र के जीवन पर नुमायां असर पड़ा। मायूसी और बेहिसी की जगह जो एतमाद पैदा हुआ उससे हमें महसूस हुआ कि अगर हममें एकता और डिसिप्लिन हो और अपनी शक्ति को जाया न होने दें तो हम अपनी समस्याओं को कामयाबी से हल कर सकते हैं।

जनता ने सरकार द्वारा उठाये गए कदमों की भरपूर ताईद की है और देश की फिज़ा में आई हुई तबदीली का स्वागत किया है। इससे उत्साहित होकर सरकार ने बहुत से मामलों में फैसलाकुन कार्रवाई की है। इन्फ्लेशन पर काबू पा लिया गया है। सितम्बर, 1974 में बहुत बढ़ी हुई कीमतों के मुकाबले में औसतन दस फीसदी गिरावट आई है और खाने-पीने की चीजों की कीमतों में तकरीबन 20 फीसदी कमी हुई है। आर्थिक अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गयी। 1973 में और 1974 के शुरू में कोयला, बिजली, इस्पात और सीमेंट जैसी चीजों की कमी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गड़बड़ी और खराब कार कर्दगी से हमारी अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा था। इस साल उत्पादन बढ़ा है और इन सभी क्षेत्रों के काम में नुमायां सुधार हुआ है। मजदूरों के सहयोग से कुछ को छोड़कर, सभी उद्योगों में, शांति रही है। हमारी इक्तिसादी हालत में जो बहुत से डिस्टार्शन्ज़ और इमबैलेंसिज पैदा हो गये थे उनमें सुधार हुआ है। इसकी वजह से कुछ तबकों के जो विशेषाधिकार थे उनमें कमी हुई है। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि कोई भी तबका अलग रह कर सिर्फ अपने ही हितों को नहीं बढ़ा सकता। हर एक तबके की भलाई का दारोमदार मजमुई इक्तिसादी मजबूती पर ही है।

गरीबों की वहबूदी के प्रोग्रामों में एक नई जान डाली गयी है। जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उन्हें घर बनाने के लिए जमीन दिलाने, भूमि सुधार लागू करने, खेती-बाड़ी पर काम करने वालों की मजदूरी बढ़ाने और कर्जे से राहत दिलाने के काम तेजी से आगे बढ़ाये जा रहे हैं।

गरीबी का हल थोड़े अर्से में नहीं निकाला जा सकता। लगातार कड़ी मेहनत और जिन्दगी के सभी शोबों में डिसिप्लिन से ही इसमें तबदीली लायी जा सकती है। इसलिए पिछले महीनों में जो नया जोश पैदा हुआ है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए और उसे जारी रखना है।

20-सूत्रीय आर्थिक प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल किया जायेगा। सरकार जनता का पूरा सहयोग चाहती है, क्योंकि यह जनता का प्रोग्राम है और इसे सिर्फ सरकारी एजेंसियों से ही नहीं चलाया जा सकता।

इस साल जैसी खरीफ की फसल पहले कभी नहीं हुई। अनाज की ज्यादा से ज्यादा वसूली की जाएगी ताकि किसान प्रोक्योर्मेंट प्राइस से कम पर अनाज बेचने पर मजबूर न हो और साथ ही साथ नागहानी जरूरत के लिए हमारे पास काफी स्टाक हो।

हम चाहते हैं कि 1979 के पहले ही और 50 लाख हैक्टेयर की सिंचाई का इन्तजाम हो सके। राज्यों के आपसी झगड़ों की वजह से कई प्रोजेक्टों को शुरू करने में देरी हुई है। सरकार इस उसूल को मनवाने की कोशिश करेगी कि पानी राष्ट्रीय सम्पत्ति है जिसका इस्तेमाल देश के बेहतरीन फायदे के लिए होना चाहिए। नदी घाटियों के मास्टर प्लान को तैयार करने के लिए एक नेशनल वाटर रिसोर्सिज़ कौंसिल काफी इख्त्यारात के साथ कायम की जाएगी। इस अर्से में, संबंधित राज्यों को एक साथ ला करके ज्यादा से ज्यादा विवादों को निपटाने की तेजी से कोशिश की जा रही है। इसी कोशिश का नतीजा है कि नर्मदा घाटी के कुछ प्रोजेक्ट, बेतवा नदी पर राजघाट प्रोजेक्ट और माही नदी पर कदाना प्रोजेक्ट के संबंध में समझौते हो गए हैं। हाल ही में, गोदावरी नदी के पानी के अधिक भाग के इस्तेमाल के संबंध में पांच राज्यों के बीच हुआ समझौता, राज्यों के दरम्यान पानी संबंधी विवादों को बातचीत के जरिये हल करने की दिशा में एक अहम कदम है। गोदावरी घाटी देश के रकबे का दसवां हिस्सा है और इस समझौते से पचास लाख हैक्टेयर जमीन की सिंचाई करने के प्रोजेक्ट बनाने में मदद मिलेगी।

इस साल सालाना योजना के लिए पिछले साल के मुकाबले में 25 फीसदी ज्यादा का प्रावधान है। प्राथमिक क्षेत्रों पर बल दिए जाने को ध्यान में रखते हुए इसे अगले साल और बढ़ाया जायेगा ताकि विकास की तहरीक में और तेजी आये। साथ ही साथ कपड़े और चीनी जैसे उद्योगों को, जो जनता की आम जरूरतों को पूरा करते हैं और जिनकी मशीनें पुरानी हो चुकी हैं, जदीद बनाने के लिए कदम उठाये जायेंगे।

सनअती लाइसैंसिंग की पालिसी और उसके काम करने के तरीकों पर फिर से गौर किया जा रहा है। आर्थिक शक्ति को कुछ ही हाथों में जमा होने पर रोकथाम लगाने की नीति का पालन करते हुए, प्राथमिक क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने और नई सनअतों को बढ़ावा देने की खातिर ऐसे कन्ट्रोल हटा दिये जायेंगे जिनकी अब जरूरत नहीं है।

पिछले 3 सालों की अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाओं की वजह से हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पर भारी बोझ पड़ा है। इकत्सादी हालत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निर्यात में काफी इजाफा जरूरी है। निर्यात बढ़ाने के लिए हाल ही में कई कदम उठाये गए हैं। हैंडलूम और दस्तकारी की चीजों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों की मदद से खास कदम उठाए जायेंगे। रुकावटों और कमियों को दूर करने के लिए नीति और काम के तरीकों पर गौर किया जा रहा है।

इन्तजामी कार्यकुशलता को बेहतर बनाने की कोशिशों को जारी रखा जायेगा और इन्हें बढ़ाया जायेगा। हमारे इन्तजाम के तरीकों और नज़रियों में ज्यादा तबदीली नहीं हुई है, खासतौर से माली इन्तजाम में, जिसका असर सरकार के सभी क्षेत्रों की कार कर्दगी पर पड़ता है। सरकार ने माली इन्तजाम में सुधार लाने की एक मुकम्मिल योजना तैयार

करने का फैसला किया है, जिस पर इस साल से अमल होगा। यूनियन का हिसाब-किताब आडिट से अलग करके डिपार्टमेंट्स के सुपुर्द कर दिया जाएगा। तन्ख्वाह और पैन्शन की अदायगी, प्रोविडेंट फंड का हिसाब-किताब, रुपया जमा करने, निकालने और खर्च की मंजूरी के नियम और तरीकों को आसान और जदीद बनाया जाएगा। कर्मचारियों के काम करने के तरीकों का जायजा लेने के ढंग को बदलना होगा ताकि हर स्तर पर एडमिनिस्ट्रेशन अपनी कार कर्दगी के बारे में जवाबदेह और रिजल्ट-ओरिअंटिड हो।

चेचक का उन्मूलन स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी है। यह वबा दोबारा न हो, इसके लिए बड़ी निगरानी रखी जा रही है। छूत की दूसरी बीमारियों के खिलाफ भी मुहिम तेज की जा रही है।

हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले तीन सालों में जन्म दर घट कर 30 फी हजार आ जाये। इस मकसद को हासिल करने के लिए, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को जन-आन्दोलन का रूप लेना होगा। इन्सेंटिव और डिसइन्सेंटिव की नई स्कीमें तैयार की जा रही हैं, ताकि छोटे परिवार की मकबूलियत में इजाफा हो।

दूसरे देशों की तरह हमने भी 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया। बहुत से क्षेत्रों में महिलाओं के मामलों का तफसील से अध्ययन किया गया है। महिलाओं को बराबर काम के लिए बराबर उजरत दिलाने का आर्डिनेन्स इस सेशन में आपके सामने आएगा। महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार की जा रही है, जिसके अमल से उन कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी जिनकी वे शिकार हैं।

पहले सेटेलाइट "आर्यभट्ट" के निर्माण पर स्पेस साईंटिस्ट्स और इन्जीनियर्स को मैं बधाई देता हूं। देहात की जनता के हित में साइन्स और टेक्नोलॉजी को अमली तौर से इस्तेमाल में लाने के लिए सेटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलिविजन एक्सपेरीमेंट की कामयाबी एक नुमायां कदम है। इस तजुर्बे से हम टेलिविजन को गांव में जन-सम्पर्क के साधन के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में तय कर सकेंगे।

एनर्जी के नए जरियों के विकास की अहमियत को मान लिया गया है और कई क्षेत्रों में काम को तेज किया जा रहा है। बायो-गैस और सोलर एनर्जी के इस्तेमाल को ज्यादा तरजीह दी जा रही है।

अब मैं दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों के बारे में जिक्र करूंगा।

हमारा यह पक्का विश्वास है कि इस उप-महाद्वीप के सभी देशों में सामान्य और दोस्ती के ताल्लुकात आवाम की तरक्की के लिए जरूरी हैं।

बांग्लादेश में हाल की घटनाओं से हमें दु:ख और चिन्ता हुई। शेख मुजीबुर्रहमान, उनके परिवार और साथियों की बेरहमी से हत्या का हमें बड़ा दु:ख और गहरा सदमा

पहुंचा। फिर भी, हमने बांग्लादेश की घटनाओं को उस देश का अन्दरूनी मामला समझा। इसलिए, कुछ हल्कों में, जो गलत प्रचार किया जा रहा है, उससे हमें बहुत दु:ख है। दोनों देशों के नुमाइन्दों के बीच हाल की बातचीत में हमने इस बात पर फिर जोर दिया है कि हम सीमा पर शांति चाहते हैं और यह भी कि बांग्लादेश पायदार और स्वतंत्र रहे जहां सभी तबके के लोगों के हित और कल्याण की रक्षा हो सके। बांग्लादेश ने अपनी नीति बनाये रखने और अपनी जनता को, चाहे किसी भी जाति, मजहब या धर्म से ताल्लुक रखती हो, समान अधिकार देने की ख्वाहिश पर बल दिया है।

मुझे दु:ख है कि शिमला समझौते पर अमल की रफ्तार धीमी रही है, क्योंकि पाकिस्तान का रवैया निराशाजनक रहा है जो कि भारत की गलत तस्वीर पेश करने की अपनी मुहिम जारी रखे हुए है।

भूटान के साथ दोस्ती के हमारे पुराने संबंध और बढ़ रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं। चूखा पनबिजली प्रोजेक्ट का काम शुरू होने से आर्थिक सहयोग का प्रोग्राम बहुत आगे बढ़ा है।

1975 में नेपाल के महामहिम नरेश और महारानी की भारत यात्रा से उस मित्र पड़ौसी देश के साथ हमारे संबंध और मजबूत हुए। उनकी यात्रा के दौरान जो बातचीत हुई, उसका नतीजा यह निकला कि नेपाल से भारत में बहने वाली नदियों के पानी के इस्तेमाल के बारे में आपसी फायदों का बेहतर अंदाजा हुआ है।

श्रीलंका के साथ हमने अनौपचारिक बातचीत और आपसी हित के मामलों में सहयोग की परम्परा को और मजबूत किया है। बर्मा* के साथ हमने अपने आर्थिक सांस्कृतिक और विज्ञान संबंधी ताल्लुकात बढ़ाये हैं।

हमने दक्षिण पूर्व एशिया तथा जापान और पूर्व एशिया के दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की। हिन्द-चीन में बहुत दिनों से चली आ रही लड़ाई खत्म होने पर हमें खुशी हुई और हमने उस समझौते का स्वागत किया, जिसके मुताबिक वियतनाम के दोनों इलाके फिर से एक दूसरे से मिल गये। हमारा विश्वास है कि री-युनाइटिड वियतनाम और पायेदार और आर्थिक लिहाज से मजबूत कम्बोडिया और लाओस दक्षिण पूर्व एशिया में शांति और इस्तेहकाम का बाईस होंगे। मैंने मार्च, 1975 में इन्डोनेशिया की यात्रा की, और पाया कि इन्डोनेशिया और भारत के बीच आपसी हित के आर्थिक, सनअती और तकनीकी सहयोग के फायदे का अहसास बढ़ रहा है।

तारीखी और सांस्कृतिक समानता और मौजूदा मसलों पर एक जैसे नज़रिये के आधार पर अफगानिस्तान के साथ हमारे करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। हमें खुशी है कि टेक्नीकल और आर्थिक सहयोग के प्रोग्राम में अच्छी तरक्की हो रही है।

*अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है।

ईरान के साथ एक दूसरे के नज़रिये को बेहतर समझने और आपसी हित के मामलों में हमारे आदान-प्रदान बढ़े और फैले। कुदरेमुख आयरन ओर प्रोजेक्ट के विकास के लिए समझौतों पर दस्तखत होना इस सिलसिले में एक नुमायां कदम है।

अरब देशों के साथ आर्थिक, तिजारती और सांस्कृतिक संबंध बढ़ रहे हैं। मिस्र, अरब गणराज्य और सूडान यात्रा से मुझे पश्चिम एशिया की समस्याओं को और गहराई से समझने का मौका मिला। सरकार अपने इस विश्वास पर फिर जोर देती है कि जब तक ताकत के जोर से कब्जा की हुई अरबों की जमीन को खाली नहीं किया जाता और फिलिस्तीनियों को उनके जाइज़ हक वापिस नहीं दिये जाते, तब तक पश्चिम एशिया में पायेदार अमन कायम नहीं हो सकता।

मोजाम्बिक, अंगोला, केप बर्डे, सन तोमे और प्रिंसिपे को सदियों पुरानी पुर्तगाली कालोनियलिज्म से आजादी हासिल करने पर हम बधाई देते हैं। साथ ही, कमोरोस, सूरीनाम और पपुआ न्यू गिनि के स्वतंत्र होने का हम स्वागत करते हैं।

हम अंगोला के अन्दरूनी मामलों में दक्षिण अफ्रीका की हथियारबन्द मदाखलत की निन्दा करते हैं। भारत ने अफ्रीकी एकता संगठन का बराबर समर्थन किया है और अपार्थाइड को खत्म करने, नमीबिया को आजाद कराने, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका में माइनोरेटी रूल खत्म करने की सभी कोशिशों में भारत अफ्रीका का साथ देगा।

सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भारत के संबंध गहरी दोस्ती, समझबूझ और बढ़ते हुए क्षेत्रों में आपसी हित में सहयोग की बुनियाद पर कायम हैं। इन देशों ने सभी अहम मामलों में भारत का हमेशा समर्थन किया है। पिछले महीनों में कई बड़े नुमाइन्दे एक-दूसरे के देश गये और मैंने हंगरी और यूगोस्लाविया की यात्रा की।

यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन की कामयाबी पायेदार शांति की तरफ एक अहम कदम है। तनाव कम करने की यह भावना दुनिया के उन देशों में भी फैलनी चाहिए जहां झगड़ा और तनाव अब भी है। ई.ई.सी. और पश्चिम यूरोप के दूसरे देशों के साथ व्यापार और साइंस टैक्नोलोजी के क्षेत्रों में हमारे आर्थिक सहयोग और संबंध बढ़ रहे हैं।

हम चाहते हैं कि यू.एस.ए. के साथ हमारे संबंध पक्के और अमल पजीर हों। शांति, पायेदारी और सहयोग को मजबूत बनाने के लिए एक-दूसरे के विचारों को समझने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए।

नॉन-एलाइन्ड देशों के राज्याध्यक्षों का अगला सम्मेलन इस साल अगस्त में श्रीलंका में होगा। हमें खुशी है कि नॉन-एलाइन्मैंट को व्यापक रूप से मान्यता मिली है। लेकिन साथ कुछ ऐसी कोशिशें भी की जा रही हैं कि नॉन-एलाइन्ड मूवमैन्ट

कमजोर और धीमी हो। हम गुटों से दूर रहने के बुनियादी उसूलों और नॉन-एलाइन्ड देशों की एकता और प्रभाव बनाये रखने के लिए कोशिशें करते रहेंगे।

दुनिया की अर्थव्यवस्था की सबसे खटकने वाली बात यह है कि इस पर कुछ अमीर देश हावी हैं और सारा बोझ गरीब और विकासशील देशों को सहना पड़ता है। ज्यों-ज्यों समय गुजरता है, उन देशों की समस्यायें और भी कठिन होती जा रही हैं। इस रुख को जल्दी बदलना होगा और ऐसे उपाय करने होंगे जिनसे दुनिया में एक नयी अर्थव्यवस्था कायम हो सके। यू.एन. जनरल असेम्बली के सातवें विशेष अधिवेशन में सबका इत्तेफाक राय होना आपसी बातचीत की शुरुआत में एक कदम है। एनर्जी, कच्चे माल और सनअती पैदावार की कीमतें मुकर्रर करने के लिए और गरीब देशों के आर्थिक विकास की समस्याओं का उचित हल निकालने की गरज से हमने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग पर पेरिस सम्मेलन में तामीरी हिस्सा लिया। हमें उम्मीद है कि सभी संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मंचों में कार्रवाई के लिए जल्द-से-जल्द ठोस समझौते हो जायेंगे।

माननीय सदस्यगण, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में, खास कर हमारे सब-कोंटिनैंट और पड़ोसी देशों में गैर-यकीनी हालत का होना देश में विघटनकारी शक्तियों की चुनौती का जारी रहना और सामाजिक और आर्थिक प्रोग्रामों को तेज करने की जरूरत मानते हुए राष्ट्र को चौकस और अनुशासित रहना होगा। कार्य कुशलता बढ़ाने और राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र में तबदीली और सुधार लाने की लगातार कोशिश जारी रहनी चाहिए।

खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि चासनाला कोयला खान का दर्दनाक वाकया, जिसकी मिसाल नहीं मिलती, का जिक्र करूं जिससे सारे देश में गहरा रंज छा गया है। खान से पानी निकालने का काम जारी है। बहुत से दोस्त मुल्क और देश में कई संस्थायें इस काम में मदद पहुंचाने के लिए आगे आईं। जिन परिवारों पर इस दुर्घटना से मुसीबत आई है उनकी तकलीफें दूर करने और खान मजदूरों की सुरक्षा के इन्तजाम में सुधार लाने के लिए सरकार कोई दकीका बाकी न रखेगी।

आपका यह अधिवेशन मुख्तसर होगा, लेकिन इसका एजेन्डा भारी है। पिछले सेशन के बकाया मामलों तथा आर्डिनैन्सों को पार्लियामेंट के एक्टों में बदलने के अलावा आपको इस अधिवेशन में पेश किये जाने वाले अर्बन लैण्ड संबंधी बिल पर विचार करना है। ऐसा वक्त है कि एक मिनट भी जाया नहीं किया जा सकता। मुझे यकीन है कि आप साफ, साहसपूर्ण और मजबूत रहनुमाई करेंगे, जिसकी जनता आपसे आशा रखती है। मैं आपको इन अहम कामों को शुरू करने की दावत देता हूं और आपकी सफलता की कामना करता हूं।

जय हिन्द।

# श्री फखरुद्दीन अली अहमद